ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास

2306. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कर और उन्हें ग्रामीण उद्योगों के रूप में विकसित कर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय और विदेशी बहुद्देशीय कंपनियों को पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है, यदि हां, तो उन कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक अनुमति प्रदान की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण आय में वृद्धि करना और ग्रामीण रोजगार में अत्यधिक वृद्धि करने की व्यवस्था करना शामिल है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों और कार्य-कलापों का उद्देश्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पहले उपलब्ध कराई जा चुकी सुविधाओं के अलावा 1989-90 के बजट प्रस्तावों में कुक्कुट दाने के अवयवों पर आयात शुल्क में कमी करना , रेफ्रिजेरेटिड ट्रांसपोर्ट की मशीनरी पर उत्पाद शुल्क में कमी करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुछ उपकरणों पर सीमा शुल्क में कमी करना शामिल है ।

(ग) जुलाई, 1988 से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विदेशी सहयोग करने से संबंधित 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है ।

मौजूदा बीज आयात नीति में परिवर्तन

2307. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की ओर से सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि मौजूदा बीज आयात नीति में परिवर्तन किया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन वैज्ञानिकों के विचार में इस नीति से हमारा स्वदेशी बीज उत्पादन प्रभावित हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन वैज्ञानिकों से इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श कर बीज आयात निति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्राप्त सुझावों के आधार पर बीज विकास संबंधी नई नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सरकार आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण जारी कर देती है ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन योजनाएं

2308. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन कितनी योजनाएं चलायी जा रही हैं और उनके लिए कितने धन का आबटन किया गया है ;

(ख) क्या राज्य की कुछ अन्य योजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हुई हैं;

(ग) ऐसे बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें इस योजनाओं के अधीन रोजगार मिलेगा और इन्हें कितने दिनों के लिए मिलेगा;

(घ) कुल बेरोजगारों की तुलना में उपरोक्त (ग) के बेरोजगारों की संख्या का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए अन्य कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): पुजारी) : (क) 1 अप्रैल, 1989 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया है । इसलिए चालू वित्तीय वर्ष से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए ससाधनों के आवटन को समाप्त कर दिया गया है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 25618.79 लाख रुपए के संसाधन (राज्य अंश सहित) आवटित किए गए हैं ।

(ख) जहां तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का संबंध है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश की गई कोई योजना/परियोजना भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है । जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत योजनाओं/निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकार संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को है ।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार का हिसाब श्रम दिवसों के रूप में लगाया जाना है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित संसाधनों से 1118.72 लाख श्रम दिवसों का रोजगार सृजित होने की सम्भावना है इससे प्रति व्यक्ति 100 दिनों की दर से लगभग 11.18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ।

(घ) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार पाने वालों का प्रतिशत लगभग 35 प्रतिशत होगा ।

(ङ) जवाहर रोजगार योजना के अलावा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु योजना ऐसे अन्य प्रमुख कार्यक्रम हैं जो बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में तांबे के कारखाने की स्थापना

2309. **श्री अजीत जोगी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलंजखण्ड खानों से तांबा अयस्क निकाल कर उससे तांबा बनाने के लिये राजस्थान के खेतड़ी कारखाने में भेजा जाता है;

(ख) क्या सरकार राज्य के पिछड़े हुए आदिवासी जिलों के औद्योगीकरण के हित में मध्य प्रदेश में ही तांबे के कारखानों की स्थापना करने का विचार करेगी; और

(ग) क्या ऐसा करना आर्थिक व तकनीकी कारणों से भी लाभप्रद न होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट स्थित मलंजखण्ड ताम्र परियोजना के केवल तांबा सान्द्रों का उत्पादन होता है । खेतड़ी कापर कम्प्लेक्स, राजस्थान में उपलब्ध अतिरिक्त प्रद्रावण क्षमता का उपयोग मलंजखण्ड ताम्र